

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I---- 1

PART I-Section 1

माधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

र्स० 20^]

नई विल्ली, बृहस्पतिवार, अक्तूबर 13, 1977/भाष्टिवन 21, 1899

No. 202]

NEW DELHI, THURSDAY, OCTOBER 13, 1977/ASVINA 21, 1899

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में एका जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

MINISTRY OF FINANCE

(Bureau of Public Enterprises)

RESOLUTION

New Delhi, the 13th October 1977

No. 2(66)/77-BPE(GM-I).—Serious distortions have crept into the structure of pay, DA and other compensatory allowances of employees in public and private sector. These distortions have been largely the result of ad hoc approach followed in the past to the problem of periodical revision of emoluments in public enterprises and in organised private industry. Moreover, a major part of the employment in the country is in the rural sector. The incomes of the vast majority of the people in agricultural sector are low and are also hable to serious fluctuations. Any rationalisation of the existing pattern of wages and incomes in different sectors can however be attempted only as an element of Integrated Policy on Wages, Incomes and Prices

2 The Government of India has, therefore, decided that a comprehensive study on wages, incomes and prices policy should be undertaken immediately. Consequently the Government hereby sets up a Study Group on Wages, Incomes and Prices, composed of the following:—

Chairman

1. Shri S Bhoothalingam, Formerly Secretary, Deptt of Economic Affairs.

Members

- 2. Dr Dharm Narain, Chairman, Agricultural Prices Commission, New > Delhi
- 3 Shri Arvind Buch, Textile Labour Association, Ahmedabad
- 4. Shri Hiten Bhaya, Director, Indian Institute of Management, Calcutta.
- 5 Prof Samuel Paul, Director, Indian Institute of Management, Ahmedabad.

Member-Secretary

- 6 Shri G C Katoch, Financial Adviser, Ministry of Defence, New Delhi.
- 3. The Study Group will prepare a draft policy on Wages, Incomes and Prices. In framing this draft policy, the Study Group will consider the following issues:—
 - (1) What should be the minimum wage and what should be the norms with reference to which the minimum wage should be determined
 - (11) Whether the minimum wage should be uniform or could be different as between—
 - (a) Agriculture. Industry and Services
 - (b) Organised and Unorganised Sectors
 - (c) Urban and Rural Sectors
 - (d) Between different States/regions
 - (e) Between different employers in the organised sector
 - (iii) What should be the relevant criteria for determining the differentials between minimum wage and maximum wage and whether the ratio between minimum-maximum wages should be uniform, or could be different in the sectors referred to in (ii) above.
 - (iv) What should be the criteria for determining maximum income and what relationship should exist between maximum income and maximum wages
 - (v) What should be the linkage between wages and incomes and prices, and to review in this connection the existing arrangements for regulation of dearness allowance in private and public sectors
 - (v1) What fiscal economic and other policies should be adopted for achieving objectives of the proposed policy ct wages, incomes and prices.
 - (vii) Whether any legislative changes would be required for implementing the proposed policy on wages, incomes and prices.
- 4 The Study Group will devise its own procedure. It may call for such information and take such evidence as it may consider necessary. The Government of India trust that the State Governments/Administrations of Union Territories, public and private sector undertakings, organisations of employers and workers and all other concerned organisations will extend to the Study Group full cooperation and assistance. The Ministries/Departments of Government of India will furnish such information and documents and render such assistance as may be required by the Study Group
 - 5 The Study Group will submit its report to Government within six months.

ORDER

Ordered that the Resolution be published in the Gazette of India,

Ordered also that a copy of the Resolution be communicated to the Ministries/Departments of the Government of India, State Governments/Administrations of Union Territories and all others concerned

G. RAMACHANDRAN, Secy.

वित्त मंत्रालय

(सरकारी उद्यम कार्यालव)

मं कल्प

नई दिल्ली, 13 धन्तूबर, 1977

सं० 2 (66) 77- बी॰ पी॰ ई॰ (जी॰ एम॰ - 1) .-- निजी एव सरकारी क्षेत्र के कर्मचारियों के वेतन ढांचों, मंहगाई भत्ते श्रीर अन्य प्रतिपूरक भत्तों में काफी श्रसमानताएं उत्पन्न हो गई हैं। ये श्रसमानताएं, पिछले कई सालों में, मरकारी क्षेत्र तथा निजी क्षेत्र के सगठित उद्योगों की परिलब्धियों का नियतकालिक परिणोधन करते समय नदर्थ नीति श्रपनाने के कारण पैदा हुई हैं। परन्तु देश में श्रधिकांश लोगों का रोजगार गायों में हैं। खेतीबाड़ी करने वाले ज्यादातर लोगों की श्रामदनी बहुत कम हैं श्रीर उसमें भी भारी उतार-चढ़ाव श्राते रहते हैं। श्रत वेतन, श्राय श्रीर मृत्य सबधी एक समन्वित नीति श्रपना कर ही विभिन्न क्षेत्रों में मजदूरी श्रीर श्राय के वर्तमान स्वरूप को युद्धिसंगत बनाने का सफल प्रयास विया जा सकता है।

2 श्रत. भारत सरकार ने यह निर्णय किया है कि वेतन, श्राय श्रीर मृत्य-नीति के संबंध में तरकाल ही एक सर्वागीण श्रध्ययन किया जाए। तदनुसार सरकार ने वेतन, श्राय श्रीर मृत्यों के विषय में निम्नलिखित सदस्यों का श्रध्ययन दल गठित किया है:---

ग्रध्यक्ष

1. श्री एस० भृतलिगम, भृतपूर्व सचिव, ग्राथिक कार्य विभाग।

सबस्यगरग

- 2. डा॰ धर्म नारायण अध्यक्ष, कृषि मृत्य आयोग, नई दिल्ली।
- 3. श्री श्ररविन्द बुच, कपडा श्रमिक संघ (टेक्सटाइल लेबर एस)सिएशन), ग्रहमदाबाद ।
- 4. श्री हितेन भाषा, निदेशक, भारतीय प्रबन्ध संस्थान, कलकत्ता।
- 5. प्रो० सेम्युमल पाल, निदेशक, भारतीय प्रबन्ध संस्थान, ग्रहमदाबाद ।

सदस्य-सचिष

- 6. श्री जी०सी० कटोच, वित्त सलाहकार, रक्षा मत्नालय नई दिल्ली ।
- 3. श्रध्ययन-दल वेतन, श्राय श्रौर मूल्य विषयक नीति का एक मसौदा नैयार करेगा। इस नीति का प्रारूप तैयार करने मे श्रध्ययन-दल निम्निखित मामलो पर विचार करेगा ----
 - (i) न्यूनतम वेतन कितना होना चाहिए स्रौर न्यूनतम वेतन का निर्धारण करने के लिए क्या प्रतिमान स्रपनाए जायं।
 - (ii) क्या न्यूनतम वेतन एक समान होना चाहिए या उसमे निम्नलिखिल के बीच अन्तर रखाजा सकता है--
 - (क) कृषि, उद्योग धौर सेवाएं

- (ख) सगठित ग्रौर प्रसगठित क्षत्र
- (ग) शहरी श्रीर ग्रामीण क्षेत्र
- (घ) विभिन्न राज्यो,क्षेत्रों के बीच
- (ङ) संगठित क्षेत्र के विभिन्न नियोक्ताम्रो के बीच
- (iii) न्यूनतम वेतन श्रौर ग्रिधिकतम वेतन के बीच श्रन्तर निर्धारित करने के लिए क्या सुसगत मानद इहोने चाहिए श्रौर क्या न्यूनतम वेतन श्रौर श्रिधक तम वेतन के श्रनुपात सभी क्षेत्रों के लिए एक समान होना चाहिए या ऊपर पैरा (ii) में बताये गये क्षेत्रों के बीच वह श्रलग-श्रलग रखा जा सकता है।
- (iV) प्रधिकतम श्राय का निर्धारण करने के लिए क्या मानवड श्रपनाये जाएं
 श्रीर श्रधिकतम श्राय श्रीर श्रधिकतम वेतन के बीच क्या संबंध होना चाहिए।
- (v) वेतन और आय और मृत्यों के बीच कैसे सम्बद्धता रखी जाय और इस विषय में निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्रों में महंगाई भत्ते के नियमन की वर्तमान व्यवस्था की समीक्षा।
- (Vi) प्रस्तावित वेतन, श्राय श्रौर मूल्य-नीति के उद्देण्यों की प्राप्ति के लिए क्या-क्या वित्तीय, श्राधिक श्रौर अन्य नीतिया श्रपनाई जाए।
- (vii) क्या प्रस्तावित वेतन, भ्राय स्रौर मृत्य-नीति को लागू करने के लिए कोई वैधानिक परिवर्तन करने होगे।
- 4. श्रध्ययन दल इस कार्य के लिए ग्रपनी प्रिक्रिया स्वय निर्धारण करेगा। अध्ययन दल आवश्यकतानुसार कोई भी सूचना या साक्ष्य प्राप्त कर सकेगा। भारत सरकार को यह विश्वास है कि राज्य सरकारे सधीय राज्य क्षेत्रों के प्रशासक, सरकारी श्रौर निजी क्षेत्र के उन्तरम, नियोजकों तौर कामगारों के सगठन श्रौर श्रन्य सभी संब्धित सगठन श्रध्ययन दल को पूरा सहयोग श्रौर सहायता देंगे। भारत सरकार के सभी मैत्रालय/विभाग अध्ययन दल द्वारा श्रोक्षित सभी सूचना, दस्तावेज श्रौर सहायता प्रदान करेगे।
 - 5. श्रव्ययन दल, भारत सरकार को श्रपनी रिपोर्ट छ महीने के भीतर प्रस्तुत करेगा ।

ग्रावेश]

आर्दिश है कि यह संकल्प भारत के राजपत्न मे प्रकाशित किया जाय।

यह भी स्रादेश है कि संकल्प की एक प्रति भारतसरकार के मत्रालयो_/विभागों, राज्य सरकारो संघीय राज्य क्षेत्रों के प्रशासनो स्रौर सभी संबंधित वर्ग को भेजी जाएं।

जी० रामचन्द्रन, सचिव।

महा प्रवन्धक, भारत सरकार मृद्रणालय, मिन्टो रोड, नई दिल्ली झारा मृद्रित तथा नियंत्रक, प्रकाशन विभाग, दिल्ली झारा प्रकाशित 1977

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1977